LATEST

NEWS

Election

Date : 21th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

नाम कटवाने की शिकायत • बीजेपी के 21971 प्रपत्र जमा, कांग्रेस ने सिर्फ 12 करवाए

SIR में वोटरों के नाम कटवाने में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी 1800 गुना आगे रही

जयपुर | विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) में नामों पर आपत्ति और दावों की अंतिम तिथि गुजरने के बाद निर्वाचन विभाग ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकडों के अनुसार कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने 1800 गुना अधिक नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा करवाएं है। कांग्रेस ने 12 नाम कटवाने के प्रपत्र भरें है । भाजपा की तरफ से 21971 नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा कराएं है। एसआईआर में प्रदेश में कुल 1.42 लाख नाम कटवाने को लेकर शिकायत और आपत्तियां दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ 12 लाख 83 हजार नाम नए जोड़ने को लेकर प्रपत्रों पर दावे आएं है। इन दावों में चुनाव क्षेत्र से अपना नाम स्थानांतरित (शिफ्ट) करने वाले लोग और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा शामिल हैं। गौरतलब है कि एसआईआर में प्रदेश में 41.85 लाख नाम काटे गए थे और उसके बाद मतदाता सूची को लेकर आपत्ति और दावों की प्रक्रिया अपनाई गई थी। बीजेपी की ओर से इस काम में 2316 बूथ लेवल एजेंट सक्रिय रहे जबकि कांग्रेस के 111 ही सक्रियता से आपत्ति और दावें दर्ज कराने में रहे।

दिल्ली तक विवाद पहुंचा दिया

बीजेपी की ओर से फर्जी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाकर कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में कई जिलों में जिला प्रशासनों को ज्ञापन देकर आपत्तियां दर्ज कराई। वहीं दिल्ली पहुंचकर भी राजस्थान में चले घटनाक्रम को लेकर देशभर में सुर्खियां बटोरी गई।

आगे क्या : जिनके नाम जोड़ने के दावे है, उनका मतदाता सूची में नाम आना लगभग तय है। हालांकि इसके लिए प्रशासन जांच की प्रक्रिया भी अपनाएंगा। उधर नाम काटने के दावों में संबंधित ईआरओ इस केस को देखेगा। संदिग्धता के आधार पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद एक कमेटी सुनवाई करके निर्णय लेगी कि वोटर का नाम काटना है या नहीं। किसी एक व्यक्ति के स्तर पर ये तय नहीं होगा।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 21 Jan 2026 - Page 10

सात हजार मतदाताओं के नाम काटने की फर्जी आपत्तियां

कांग्रेस ने भाजपा बीएलए सहित सबूत पेश कर किया खुलासा

कासं/अजमेर। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने मंगलवार को अजमेर में विशेष गहन पुनरीक्षण में गत तीन दिनों में फर्जी आपत्तियों के आधार पर 7 हजार मतदाताओं के नाम काटने पर नाराजगी व्यक्त कर जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। राठौड़ ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी से आग्रह किया कि इन आपत्तियों को तुरंत हटाकर लोगों के नाम यथावत रखे जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों और इस साजिश में लिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने प्रेसवार्ता कर मीडिया के समक्ष बीएलए के नाम से फर्जी शिकायत लेकर मतदाता सूचियों में नाम कटवाने का खुलासा दस्तावेजी सबूतों के साथ किया। राठौड़ ने तीन दिनों में सात हजार मतदाताओं को मिले नोटिस से संबंधित दस्तावेज बताते हुए भाजपा द्वारा नियुक्त एक बीएलए राधेश्याम को मीडिया के समक्ष पेश किया जिसने मीडिया के सामने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई। मेरे फर्जी साइन है, मैं किसी के नाम कटवाने नहीं गया। राठौड़ ने आरोप लगाया कि शिकायत के बिना मतदाता सूची से सात हजार लोगों के नाम काटने का प्रयास किया गया है। उन्होंने नौसर क्षेत्र की मतदाता सूची के भाग संख्या 25 (नई 31) के बीएलए पवन मिश्रा का वीडियो के जरिए उसके फर्जी दस्तखत से 141 फार्म जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने भाग संख्या 72 के बीएलए द्वारा उसके फर्जी दस्तखत से फार्म जारी होने की जानकारी भी दी।

पंजाब केसरी
WED,21 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 6

आठ विधानसभाओं में SIR की प्रगति पर पारदर्शिता की मांग

डेटा को लेकर कांग्रेस का दबाव, ज्ञापन सौंपा

जयपुर, 20 जनवरी (विसं): विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही है। इसी क्रम में जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने 8 विधानसभाओं का डेटा प्राप्त करने के लिए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा।

संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी की अगुवाई में हवामहल, किशनपोल, आदर्श

नगर, सिविल लाइंस, सांगानेर, मालवीय नगर, बगरू, विद्याधर नगर के मतदाताओं के वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट नामों के हटाने तथा नए मतदाताओं को जोड़ने के कार्य का डेटा मांगने के लिए यह ज्ञापन दिया गया।

नेहरू ने कहा कि भाजपा पार्टी की बौखलाई हुई सरकार एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव करवा सकती है, ऐसा हुआ तो जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी कानूनी कार्रवाई करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान मो. सलीम, शेख महबूब जड़ावता, रमेश कुमावत, एडवोकेट राजेश जाजोरिया, प्रकाश चंद कानूनगो, कैलाश खारड़ा, हरेंद्रपाल सिंह जादौन, बद्रीनारायण कुमावत, दिनेश गुप्ता, हेमलता सिंह फौजदार सहित कई पदाधिकारी व वर्कर्स उपस्थित रहे। कन्क्लुजन यह कि कांग्रेस एसआईआर पर सतत निगरानी और पारदर्शिता की मांग कर रही है।

Cong produces 'proof' of forged SIR forms in Ajmer

TIMES NEWS NETWORK

Shaukat Ahmed

(L to R) Cong councillor Shahja Bibi, Cong Ajmer city prez Rajkumar Jaipal, ex-RTDC chairman Dharmendra Rathore, and booth-level agent Radhey Shyam Banjara at a press conference in Ajmer Tuesday

Ajmer: Ajmer unit of Congress Tuesday claimed "evidence" of mass deletion of voters under the Special Intensive Revision (SIR) on directions of BJP. Addressing a press conference, Cong disrtict president Rajkumar Jaipal and senior functionary Dharmendra Rathore showed messages from the official WhatsApp group of booth level officers (BLOs) where they complained about the misuse of Form 7 for deleting names of voters.

Among those deleted from the rolls is Shahjahan Biwi, the sitting municipal councillor from Ward 12. Congress also produced BJP's booth level agent (BLA) Radhye Shyam Banjara at the presser, who claimed that the Form 7 submitted in his name did not have his signature.

"We now have evidence that our leader Rahul Gandhi has been speaking about, that the election commission on the directions of BJP is forging the voters' list," Rathore said, holding up a copy of the official WhatsApp group of BLOs, in which district election officers and other officials were also included.

"One of the BLO is writing that in ward number 176 there are 993 voters and he got Form 7 to delete names of 467 voters. When the BLO went on the ground, he faced the anger of people because the Form 7 which was submitted had no information of the complainant," Rathore said, reading out from the group chat.

"Another BLO is saying that the Form 7 does not have the identity of the complainant. Many BLOs demanded from the election officer to take action against those who are forging Form 7 and pressurising them to delete names of voters," Rathore said.

Rathore produced three letters from BLAs Amit Dayma, Vikky Khateek, and Radhye Shyam Banjara, in which they claimed that they did not give any Form 7. "No BLA can file more than 10 Form 7, but here the BLOs are getting such forms in bulk, which shows how BJP is forging the voters' list," Rathore said.

SIR: Barmer voters allege mass deletions

TOI

TIMES NEWS NETWORK

Ex-MLA Mewa Ram Jain submits a memorandum to Barmer dist collector Tina Dabi Tuesday

Jaisalmer: Led by former MLA Mewa Ram Jain, hundreds of people raised slogans in front of the Barmer district collectorate office Tuesday against alleged deletion of thousands of voters' names during the Special Intensive Revision (SIR) process. On Monday, Baytoo MLA Harish Chaudhary along with Barmer MP Ummeda Ram Beniwal had led locals in a protest and submitted a memorandum to the district collector.

On Tuesday, Jain alleged that under SIR, a large number of voters were removed in several wards of Barmer city, including Vishala, Dudaberi, Malwa and Lakhetali. He claimed that many voters who resided at the same address for years and regularly voted in the past found their names suddenly removed.

After the protest, a delegation met the district collector and submitted a memorandum demanding a thorough investigation into all names removed from the voter list and the immediate re-addition of those deleted without valid reason. The delegation also requested that transparency and public information be prioritised during processes like SIR in the future.

Protesters also met the sub-divisional officer and registered objections, alleging that in many areas names were deleted by booth level officers without proper notice, despite rules requiring notice and verification. District collector Tina Dabi assured the matter would be seriously investigated.

Hindustan Times

Ex-Cong councillor claims BJP BLA tried to delete his name from rolls

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: A former Congress councillor in Jaipur on Monday submitted a complaint to the Lalkothi police station against a BJP booth-level agent for allegedly conspiring to delete his name from the electoral rolls during the special intensive revision (SIR) exercise, police said on Tuesday.

Lalkothi SHO, Prakash Ram, said, "No FIR has been lodged yet. It is a matter under the Jaipur city SDM and the Election Department. We have suggested that he approach them."

A SENIOR ELECTION DEPT OFFICIAL SAID THAT THE CASE WAS YET TO BE REPORTED TO THEM, BUT ASSURED ACTION INTO THE MATTER

According to the police, the former councillor, Akbar Uddin, from ward number 89 of Adarsh Nagar, in his complaint letter, alleged that the brother of a local BJP BLA, Ashok Kumar, allegedly submitted a forged form-7 in his name to that effect. According to the complaint, "a fake declaration has also been attached with the form saying that I permanently shifted to another address. However, my family has stayed at their ancestral house in Adarsh Nagar for over 100 years."

A senior officer from the Election Department said, "No such case has yet been reported to us. However, we will look into the matter."Jaipur district collector Jitendra Soni did not respond to requests for comment.

SIR hearing in SC turns into a debate on 'decolonisation'

Ananthakrishnan G
New Delhi, January 20

THE HEARING on Tuesday before the Supreme Court on the constitutional validity of the Special Intensive Revision (SIR) being carried out by the Election Commission turned into a discussion on decolonisation. Senior Advocate Rakesh Dwivedi, appearing for the poll panel, wondered why a 1977 judgment had to quote "colonisers of India" like Britain's war-time Prime Minister Winston Churchill - to which the bench said there is this idea that democracy is imported into India, and that might not be historically correct.

Dwivedi referred to the 1977 Supreme Court Constitution Bench ruling in the Mohinder Singh Gill & Another Vs The Chief Election Commissioner, New Delhi, saying it "completely knocks the bottom of" some of the arguments put forth by the petitioners. The senior counsel told the bench of CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi that in the case, "the exercise of powers by the Election Commission was upheld". He, however, added, "But I am wondering why the court had to refer to Winston Churchill and William Pitt, the colonisers of India, in order to draw support for this proposition." The judgment, authored by late Justice V R Krishna Iyer, had cited former British prime ministers Churchill, Pitt and Benjamin Disraeli.

Justice Bagchi said, "This idea is that democracy has been imported into India, which perhaps may not be a historically correct fact." He added, "There were democratic republics even before the birth of Christ... In fact, the Pal dynasty in Bengal had representative kinship. So, the king was not the son of the preceding king. He was elected by the noblemen. Bihar, which you are arguing (the SIR matter before the court began with challenges to the exercise conducted by the EC in Bihar), has been the bedrock of democracy. Number of these city states were democratic states."

> **"I'm wondering why the court had to refer to Winston Churchill and William Pitt, the colonisers of India, in order to draw support for this proposition."**
>
> **RAKESH DWIVEDI,** SENIOR ADVOCATE

Dwivedi said, "This idea of Churchill was meant only for Britain, not for India. Whatever they were saying, they had democracy in Britain, but colony in India." He added, "All that I wish to say is that when you quote something, there are much more appropriate (people to be quoted)...The idea need not have support of Churchill, the original idea itself is sufficient."

Justice Bagchi said, "When you see the history of democracy in (the) UK, it was elitist democracy. People holding properties were permitted to vote. That is what was transposed in the Government of India Act which you started your submissions on... So, the Constitution does not actually copy the democracy which was envisaged (in the Government of India Act)."

Seconding the view, Dwivedi said, "It's an incorrect formulation (to say the Constitution is a copy of the Government of India Act) that just because the three schedules are there, and some other provisions... (they are) completely different, the underlying spirit is different."

Justice Bagchi said CJI Kant's judgment upholding Section 6A of the Citizenship Act "has been most illuminating" on the subject of fraternity and equality. Agreeing, Dwivedi said, "We need to break away from the colonised mindset. Decolonsiation of mindset is important."

एसआइआर | दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि तक निर्वाचन विभाग को मिले आवेदन

10.92 लाख नाम जोड़ने, 1.17 लाख हटाने की अर्जी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश में एसआइआर अभियान के तहत दावे-आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि तक निर्वाचन विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग को नाम जोड़ने के लिए कुल 10,92,456 आवेदन और नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए 1,17,691 फॉर्म मिले हैं। दावे-आपत्तियों की सुनवाई के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। विभाग के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में सबसे अधिक आवेदन सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से प्राप्त हुए हैं।

5,46,56,215
फॉर्म वितरित

5,04,71,369
फॉर्म जमा

41,84,819
नाम हटाए

इतने मिले आवेदन

	नाम जोड़ने	नाम हटाने
कुल आवेदन	10,92,456	1,17,691
भाजपा ने दिए	316	21,971
कांग्रेस ने दिए	185	12
बीएपी ने दिए	2	—

**16 दिसंबर को जारी एसआइआर ड्राफ्ट रोल के अनुसार मतदाताओं की स्थिति*

भाजपा-कांग्रेस एसआइआर पर आमने-सामने

कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआइआर में कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि आयोग अपना निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। कांग्रेस एसआइआर में गड़बड़ी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन को भी ज्ञापन सौंप चुकी है।

दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि तक निर्वाचन विभाग को मिले आवेदन

एसआइआर अभियान : 10.92 लाख नाम जोड़ने के आवेदन, 1.17 लाख हटाने के फॉर्म

5,46,56,215 फॉर्म वितरित

5,04,71,369 फॉर्म जमा

41,84,819 नाम हटाए

**16 दिसंबर को जारी एसआइआर ड्राफ्ट रोल के अनुसार मतदाताओं की स्थिति*

इतने मिले आवेदन

	नाम जोड़ने	नाम हटाने
कुल आवेदन	10,92,456	1,17,691
भाजपा ने दिए	316	21,971
कांग्रेस ने दिए	185	12
बीएपी ने दिए	2	--

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश में एसआइआर अभियान के तहत दावे-आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि तक निर्वाचन विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग को नाम जोड़ने के लिए कुल 10,92,456 आवेदन और नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए 1,17,691 फॉर्म मिले हैं।

दावे-आपत्तियों की सुनवाई के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। विभाग के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में सबसे अधिक आवेदन सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से प्राप्त हुए हैं।

भाजपा-कांग्रेस एसआइआर पर आमने-सामने

कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआइआर में कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि आयोग अपना निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। कांग्रेस एसआइआर में गड़बड़ी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन को भी ज्ञापन सौंप चुकी है।

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2026 राजस्थान की सहभागिता

चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकता पर होगा राजस्थान का प्रस्तुतिकरण

सम्मेलन में राजस्थान के पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया एवं कजाखिस्तान

मरुलहर न्यूज

जयपुर/बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 से 23 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र और

चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनझ2026 (IICDEM-2026) में राजस्थान भी सक्रिय सहभागिता कर रहा है। यह तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस वैश्विक सम्मेलन में राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा हचुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकताह विषय पर अपने अनुभव, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्थान ने चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की सकारात्मक भूमिका, मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री महाजन ने बताया कि इस सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान के पार्टनर देश क्रोएशिया एवं कजाखिस्तान हैं।

इन देशों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान, संवाद और सहयोग के माध्यम से चुनाव प्रबंधन, मीडिया एंगेजमेंट तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई समझ और नवाचार विकसित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन विश्वभर के लगभग 40 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग की भागीदारी न केवल राज्य के चुनावी सुधारों और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और समावेशी चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में भी योगदान देगी।

राजस्थान निर्वाचन विभाग इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लोकतंत्र, पारदर्शिता और मतदाता सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन के नेतृत्व में राजस्थान का 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है।

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2026 राजस्थान की सहभागिता

चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकता पर होगा राजस्थान का प्रस्तुतिकरण

सम्मेलन में राजस्थान के पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया एवं कजाखिस्तान

मरुमंच न्यूज

जयपुर/बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 से 23 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनझ2026 (IICDEM-2026) में राजस्थान भी सक्रिय सहभागिता कर रहा है। यह तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (III-DEM) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस वैश्विक सम्मेलन में राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा ह्चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकताह्व विषय पर अपने अनुभव, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्थान ने चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की सकारात्मक भूमिका, मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री महाजन ने बताया कि इस सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान के पार्टनर देश क्रोएशिया एवं कजाखिस्तान हैं।

इन देशों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान, संवाद और सहयोग के माध्यम से चुनाव प्रबंधन, मीडिया एंगेजमेंट तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई समझ और नवाचार विकसित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन विश्वभर के लगभग 40 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग की भागीदारी न केवल राज्य के चुनावी सुधारों और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और समावेशी चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में भी योगदान देगी।

राजस्थान निर्वाचन विभाग इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लोकतंत्र, पारदर्शिता और मतदाता सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन के नेतृत्व में राजस्थान का 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है।

चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में राजस्थान के पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया और कजाखिस्तान

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में राजस्थान भी सक्रिय सहभागिता कर रहा है। यह तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफडेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस वैश्विक सम्मेलन में राजस्थान निर्वाचन विभाग चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकता विषय पर अपने अनुभव, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को पेश करेगा। राजस्थान ने चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की सकारात्मक भूमिका, मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय काम किया है।

इस सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान के पार्टनर देश क्रोएशिया एवं कजाखस्तान हैं। इन देशों के साथ अनुभवों के आदान प्रदान, संवाद और सहयोग के माध्यम से चुनाव प्रबंधन, मीडिया एंगेजमेंट तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई समझ और नवाचार विकसित किए जाएंगे। यह सम्मेलन विश्वभर के लगभग 40 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग की भागीदारी न केवल राज्य के चुनावी सुधारों और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगी, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और समावेशी चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में भी योगदान देगी।

पचपदरा क्षेत्र में एक वर्ग विशेष के नाम काटने का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग

वोटरलिस्ट में फर्जी आपत्तियां लोकतंत्र पर हमला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बालोतरा. पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने मंगलवार को डाक बंगला बालोतरा में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने भाजपा सरकार और प्रशासन पर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाकर मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी आपत्तियां (फॉर्म नंबर 7) दर्ज कराने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। प्रजापत ने कहा कि एसआइआर के तहत जिन मतदाताओं का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से पहले ही विधिवत किया जा चुका है, अब उन्हीं सत्यापित मतदाताओं के खिलाफ उन्हीं बीएलओ से आपत्ति रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो न केवल संदेहास्पद हैं बल्कि चुनाव आयोग के नियमों और मंशा के भी विपरीत है।

पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता की।

उन्होंने बताया कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं पर यह कहकर आपत्तियां लगाई जा रही हैं कि वे श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं, जबकि वे कई पीढ़ियों से पचपदरा क्षेत्र में निवासरत हैं और उनके पास स्थायी निवास, पहचान पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नाम काटने अथवा आपत्तियां दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है कि मतदाता समय रहते अपना पक्ष न रख सकें और उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा सके। उन्होंने शासन-प्रशासन से फर्जी आपत्तियों पर तत्काल रोक लगाने, पूरे मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच कराने तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व सभापति रतनलाल खत्री, मेहबूब खान सिंधी, ठाकराराम गोदारा, अयूब कुरैशी, सलीम खिलेरी, अकबर खान, राजेश्वर प्रजापत, मोहम्मद जावेद सहित कई लोग मौजूद रहे।

udaipur express

मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के पर दिया ज्ञापन

उदयपुर (कासं)। उदयपुर शहर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के गंभीर मामले को लेकर आज अंजुमन तालीमुल इस्लाम, उदयपुर की ओर से अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में ज़िला कलेक्टर, उदयपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जॉइंट सेक्रेट्री इज़हार हुसैन ने ज़िला प्रशासन से मांग की कि मतदाता सूची में की गई सभी गड़बड़ियों को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। इस अवसर पर शहजाद हुसैन, तनवीर चिश्ती, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अय्युब, फिरोज अब्बासी, मोहम्मद अनीस, आदिल शेख, मोहम्मद अशफाक सहित अंजुमन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

उदयपुर (पुकार)। उदयपुर शहर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के गंभीर मामले को लेकर मंगलवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम, उदयपुर की ओर से अंजुमन सदर जनाब मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में ज़िला कलेक्टर, उदयपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से अंजुमन सेक्रेट्री मुस्तफा शेख ने प्रशासन का ध्यान इस अत्यंत गंभीर और द्वेषपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि मतदान जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से किसी विशेष समुदाय को वंचित करना न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। इस अवसर पर शहजाद हुसैन, तनवीर चिश्ती, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अय्युब, फिरोज अब्बासी, मोहम्मद अनीस, आदिल शेख, मोहम्मद अशफाक सहित अंजुमन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रातःकाल
Udaipur City Edition | 2026-01-21 | Page- 5
epaper.pratahkal.com

र
ल्प

शिविर
उच्च
ली में
क एवं
नागदा
बालकों
व्रती का
प्राचार्य
थियों के
संस्कृत
न्न अंग
शिविर
स्थाओं
कंसारा,
ीवाल,
शंकर
कुलदीप
शर्मा,
ों का

मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

उदयपुर (वि.)। शहर में चल रही एआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के गंभीर मामले को लेकर मंगलवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम की ओर से अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में ज़िला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंजुमन सेक्रेट्री मुस्तफा शेख ने बताया कि मतदान जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से किसी विशेष समुदाय को वंचित करना न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार हैं। ज्ञापन में अंजुमन तालीमुल इस्लाम की कैबिनेट, जनरल हाउस के सदस्यों एवं शहर के मोतबीर नागरिकों की ओर से यह प्रमुख मांग रखी गई कि जिन झ्ख्ल (बूथ लेवल अधिकारियों) द्वारा मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन स्वसंज्ञान लेकर सख़्त कानूनी कार्रवाई करे। अंजुमन नायब सदर फारूक कुरैशी ने उदयपुर विधायक श्री ताराचंद जैन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की।

ना प्रबन्धक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, सलुम्बर
E-mail sewdsc.salumber@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक नवज्योति
Udaipur City - 21 Jan 2026 - Page 7

मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटाने से आक्रोश,सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो नवज्योति,उदयपुर। अंजुमन तालीमुल इस्लाम सदर मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में कलक्टर को ज्ञापन देकर शहर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध जताया। ज्ञापन में मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। अंजुमन सेक्रेट्री मुस्तफा शेख ने कहा कि मतदान जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से किसी विशेष समुदाय को वंचित करना न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। अंजुमन नायब सदर फारूक कुरैशी ने शहर विधायक ताराचंद जैन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की। अंजुमन के वरिष्ठ सदस्य रियाज हुसैन ने कहा कि यदि समय रहते इस प्रकार की द्वेषपूर्ण गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगी। वहीं, जनरल हाउस सदस्य उमर फारूक ने आम नागरिकों से लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की अपील की। जॉइंट सेक्रेट्री इज़हार हुसैन ने जिला प्रशासन से मतदाता सूची में की गई सभी गड़बड़ियों को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने तथा किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की मांग की। इस अवसर पर शहजाद हुसैन, तनवीर चिश्ती, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अय्यूब, फिरोज अब्बासी, मोहम्मद अनीस, आदिल शेख, मोहम्मद अशफाक सहित अंजुमन के अनेक

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक भास्कर उदयपुर 21-01-2026

मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने पर कार्रवाई की मांग

एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटने का आरोप, ज्ञापन सौंपा

उदयपुर। शहर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के आरोपों को लेकर अंजुमन तालीमूल इस्लाम ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में सेक्रेट्री मुस्तफा शेख ने इसे संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध बताया। नायब सदर फारूक कुरैशी ने विधायक ताराचंद जैन की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। वरिष्ठ सदस्य रियाज हुसैन ने कहा कि यदि समय रहते इस प्रकार की द्वेषपूर्ण गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगी। जॉइंट सेक्रेट्री इजहार हुसैन ने मतदाता सूची की त्रुटियां तुरंत सुधारने की मांग की। इस दौरान शहजाद हुसैन, तनवीर चिश्ती, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अय्यूब सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान पत्रिका 21.01.2026

विधायक बुडानिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे किया प्रदर्शन

नियम विरुद्ध वोट काटने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

तारानगर. मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के नियम विरुद्ध बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा कर कथित तौर पर वोट काटने की कोशिश के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे विरोध-प्रदर्शन किया। विधायक निवास पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र से एकत्रित हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के जमकर नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे व कार्यालय के आगे सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के नुमाइंदों के दबाव में आकर अधिकारियों पर वोट काटने की कोशिश करने का आरोप लगाया व जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर एसआइआर के तहत फर्जी तरीके से फार्म 7 में फर्जी हस्ताक्षर कर वोट हटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। विधायक बुडानिया के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया कि पूरे राज्य में एसआइआर का काम चल रहा है। इस काम में तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार फार्म 7 के संख्या 929 थी, लेकिन 15 जनवरी को सांय के समय में आपके कार्यालय में फार्म सं. 7 जो कॉम्प्युटराईज्ड थे जिनकी संख्या करीब 6-7 हजार हैं जो अवैध तरीके से जमा करवाए गए हैं। सभी बीएलओ को तुरंत बुलाकर देर रात 12 बजे तक उक्त 6-7 हजार फार्मों में अंकित मतदाताओं के नाम हटवाने के निर्देश दिए गए।

कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में फर्जी तरीके से जमा फार्म 7 जमा करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इस मौके पर विधायक नरेंद्र बुडानिया, निवर्तमान प्रधान संजय कस्वां, अभिषेक बुडानिया, हरिसिंह बेनीवाल, उमाशंकर शर्मा, मदन पांडिया, वेदप्रकाश सहारण, मानसिंह सैनी, मोहरसिंह ज्याणी, मुंशी तेली, कृष्ण सहारण, विमला कालवा, भागीरथ भामी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

आनन-फानन में वापस मंगवाए फॉर्म

उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारियों की ओर से बीएलओ से फार्म वापिस मंगवाए गए जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर फर्जी तरीके से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास किया गया है। बुड़ानिया ने आगे कहा कि फर्जी फॉर्म जमा करवाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया हैं। साथ ही कांग्रेस के व समुदाय विशेष के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा हैं।